स्वच्छ भारत
सम्पूर्ण स्वच्छता की ओर

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
जल शक्ति मंत्रालय
भारत सरकार
DEPARTMENT OF DRINKING WATER AND SANITATION
MINISTRY OF JAL SHAKTI
GOVERNMENT OF INDIA

Azadi Ka Amrit Mahotsav

G20

स्वच्छता समाचार

खंड 3 । अंक 8 । सितंबर 2023

स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण न्यूज़लेटर

@swachhbharat @SBMGramin @SwachhBharatMissionGramin @swachh_bharat @swachhbharatgrameen

"हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैट्रोलियम ईंधन पर निर्भरता और इसके बढ़ते आयात और उच्च कार्बन फुटप्रिंट महत्वपूर्ण आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं हैं। इसलिए उनके स्थान पर अपेक्षाकृत कम कार्बन उत्सर्जन वाले ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना समय की मांग है। इससे गोबरधन जो अपशिष्ट-से-धन (रिसोर्स) की आवश्यकता प्रतीत होती है जिसके द्वारा बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने में राष्ट्र की सहायता के लिए बायोगैस का उत्पादन किया जा सकता है, साथ-ही, 'ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन' को कम करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता में योगदान किया जा सकता है।"

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत
केंद्रीय मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय

कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं

29 अगस्त, 2023 तक

ODF+

भारत के 4,31,350 से अधिक बसे हुए गांवों ने स्वयं को ODF Plus घोषित किया है।

- उज्ज्वल: **2,86,724**
- उदयीमान: **53,076**
- उत्कृष्ट: **91,550**

2,25,066 गांवों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था सुनिश्चित हुई
3,64,464 गांवों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था सुनिश्चित हुई
777 गोबरधन संयंत्रों का कार्य देश भर में पूरा हुआ
2,207 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयों की स्थापना की गई

स्वच्छता पखवाड़ा:

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय; खेल विभाग; युवा कार्यक्रम विभाग तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 01-15 अगस्त तक स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया।

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय (MoHI) ने 16-31 अगस्त तक स्वच्छता गतिविधियां कीं। भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कोलकाता में अपने पंजीकृत कार्यालय में एक बैनर प्रदर्शित किया और स्वच्छता शपथ दिलवायी। इसके अलावा, प्लास्टिक कचरे के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया गया जिसमें आम सार्वजनिक स्थानों जैसे पार्कों, बाजारों आदि से प्लास्टिक कचरे का संग्रहण और पृथक्करण शामिल था। उनकी तंदूर स्थित इकाई में, सफाई पर एक स्वच्छता जागरूकता सत्र और 'विकसित भारत में स्वच्छता का योगदान' विषय पर कर्मचारियों के लिए एक निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसके अलावा, स्क्रैप वस्तुओं के उचित निपटान और गोदाम में अपशिष्ट पदार्थों के उचित भंडारण के लिए एक अभियान चलाया गया।

परिहार वेब पोर्टल: कर्नाटक की शिकायत निवारण प्रणाली

कर्नाटक ने ग्रामीण लोगों की जल और स्वच्छता से संबंधित शिकायतों का समाधान करने तथा ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (RDWSD), कर्नाटक सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के बारे में उनका मार्गदर्शन करने के लिए एक शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की है।

मार्च 2020 में शुरू की गई परिहार (पब्लिक एक्सेस टू रेस्पॉन्सिव एंड इनोवेटिव हैंडलिंग ऑफ कंप्लेंट रेजोल्यूशन एप्लीकेशन) हेल्पलाइन एक व्यवसायिक कॉल सेंटर है, जिसे सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच 9480985555 नंबर का उपयोग करके संपर्क किया जा सकता है। लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, ईमेल या परिहार वेबसाइट के माध्यम से भी अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं।

आवश्यकता: परिहार की स्थापना से पहले, डाक पत्रों जैसी पारंपरिक संचार विधियों के माध्यम से शिकायतें प्राप्त की जाती थीं। इससे शिकायतों को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचने में काफी समय लगता था और लोग अपने पत्रों या शिकायतों को ट्रैक करने अथवा अपने मुद्दों या समस्याओं को हल करने के लिए संबंधित अधिकारियों तक पहुंचने में असमर्थ थे।

लोग अपशिष्ट जल ठहराव, जल निकासी के मुद्दों, अपशिष्ट प्रबंधन समस्याओं, सामुदायिक या सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और प्रबंधन तथा व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण के बारे में शिकायत कर सकते हैं।

अधिक पढ़ने के लिए, **यहाँ क्लिक करें**

संपर्क करें: wsrdpr@gmail.com

गुजरात में SBM-G-II के कार्यान्वयन पर ToT

ODF के लाभों को बनाए रखने, ODF Plus में उनकी भूमिका, प्रौद्योगिकी विकल्पों का जानकारी के आधार पर चयन करने, दीर्घकालिक स्थिरता के लिए O&M और वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए गतिविधियों के बारे में ग्राम कार्यकर्ताओं की क्षमताओं के सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से 1 से 5 अगस्त, 2023 तक गुजरात के गांधीनगर जिले में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (ToT) आयोजित किया गया था।

IEC के सलाहकारों, मानव संसाधन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के क्षमता निर्माण के लिए SBM-G-II के कार्यान्वयन के संबंध में 5 दिवसीय ToT गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान (GIDM) में आयोजित की गई।

यूनिसेफ के सहयोग से राज्य में कुल 39 मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षित किया गया। गुजरात में आयोजित इस तरह के प्रशिक्षण का यह दूसरा बैच है।

प्रशिक्षण में ऐसे विषय शामिल थे जो समग्र रूप से कार्यक्रम की समझ पैदा करने और कार्यक्रम के प्रत्येक घटक – ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) पर भी केंद्रित थे ताकि गांवों में दृश्यगत स्वच्छता लाई जा सके। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया था कि संबंधित सत्रों में राज्य से जुड़े विशिष्ट परिदृश्यों पर प्रासंगिक चर्चा हो। इसमें प्रतिभागियों द्वारा समूह चर्चा और प्रस्तुतियों जैसी गतिविधियों को भी शामिल किया गया था ताकि महत्वपूर्ण सामग्री को प्रतिबिंबित किया जा सके और इसके महत्व पर पुन: जोर दिया जा सके। गतिविधियों से एक ऐसा माहौल बना जिसमें प्रतिभागियों ने चुनौतियों और उनके स्वयं के पास मौजूद संभावित समाधानों पर भी चर्चा की। तत्पश्चात, प्रशिक्षकों ने समाधानों को मान्यता दी।

अधिक पढ़ने के लिए, **यहाँ क्लिक करें**

संपर्क करें: esaste@primoveindia.com

छत्तीसगढ़ में प्रगतिशील घर-घर शौचालय अभियान

यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर घर में शौचालय हो और घर के सभी सदस्यों द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा हो, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में घर-घर शौचालय अभियान चल रहा है।

यह अभियान 1 जून से 15 अगस्त 2023 तक चलाया गया।

इस अभियान का शुभारंभ अधिक से अधिक गांवों को ODF Plus घोषित करवाने की पृष्ठभूमि के अंतर्गत आता है। इस विशेष अभियान का उद्देश्य शौचालय की पहुंच और उपयोग के संबंध में सभी ग्रामीण परिवारों का 100 प्रतिशत स्वच्छता कवरेज सुनिश्चित करना है।

ODF Sustainability अभियान से पहले, 1 से 15 जून तक, परिवारों से व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों के लिए आवेदन उनकी ग्राम पंचायत के माध्यम से एक ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त किए गए थे। इसके बाद 15 से 30 जून तक आवेदनों का सत्यापन किया गया और सत्यापित आवेदनों को प्रशासनिक मंजूरी दी गई।

राज्य को आशा है कि 15 अगस्त तक सभी निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएंगे और 15 अगस्त को ग्राम पंचायतें प्रमाण पत्र जारी करके यह घोषणा करेंगी कि उनकी संबंधित ग्राम पंचायतों में प्रत्येक परिवार को शौचालय सुविधाओं से कवर किया गया है।

अभियान का व्यापक प्रचार सुनिश्चित करने के लिए और यह निश्चित करने के लिए कि सभी परिवारों को पारिवारिक शौचालयों के लिए आवेदनों के बारे में पता है तथा उन्हें अपने शौचालयों के रखरखाव के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, एक व्यापक IEC अभियान चलाया जा रहा है। इसका प्रचार समाचार पत्रों के विज्ञापनों, घर-घर पहुंचकर, घोषणाओं और होर्डिंग्स के माध्यम से किया जा रहा है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सभी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कर्मचारियों और अन्य क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को इस अभियान में लगाया गया है।

अधिक पढ़ने के लिए, **यहाँ क्लिक करें**

संपर्क करें: rupeshrathore2000in@gmail.com

देबीपुर गांव में डेयरी फार्मों से कचरे का प्रभावी रूप से प्रबंधन

वाटरएड इंडिया ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (SBM-G) और पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले के देबीपुर गांव के लोगों की सहायता से मई 2023 में गांव के डेयरी फार्मों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक हाइब्रिड अपशिष्ट प्रबंधन मॉडल तैयार और कार्यान्वित किया।

मेमारी-I ब्लॉक के देबीपुर गांव में 3,400 घर हैं, जिनमें से कई मुख्य रूप से दूध उत्पादन के लिए मवेशी पालन के कार्य में लगे हुए हैं। हालांकि सभी घर जल निकासी सुविधा से जुड़े हुए हैं, फिर भी पशु शेड के बनने से पहले कचरे का निपटान खुले में किया जाता था। नतीजतन, आसपास के क्षेत्रों में गंदगी और बदबू थी। 50 घरों से प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले कचरे का अनुमान लगभग 10,000 लीटर था।

ग्रामीण भारत की डेयरी फार्मिंग से गांवों और शहरों में रहने वाले लोगों को दूध की आवश्यक आपूर्ति मिलती है। तथापि, खेतों के आसपास स्वच्छता और साफ-सफाई बनाए रखने में चुनौतियां हैं। छोटे आकार के कई खेत गांवों के आसपास के क्षेत्र में अवस्थित हैं, जहां अक्सर मवेशियों द्वारा उत्पन्न कचरे को खुले में विघटित होने के लिए छोड़ दिया जाता है।

वाटरएड इंडिया परियोजना टीम ने एसबीएम ग्रामीण के स्थानीय प्रतिनिधियों के परामर्श से देबीपुर में एक अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा का निर्माण किया। इसके डिजाइन में 15,000 लीटर की क्षमता वाला एक निपटान टैंक, एक बजरी बेड के साथ एक रिचार्ज ट्रेंच और छिद्रित पाइपों से युक्त एक वाष्पोत्सर्जन बेड शामिल है। एसबीएम ग्रामीण के तहत परियोजना लागत की प्रतिपूर्ति की गई।

अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा से आसपास के क्षेत्रों की स्वच्छता में सुधार हुआ है, जिसमें मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम और स्थल से अतिप्रवाह को कम करना शामिल है, जिसने नालियों को जाम कर दिया था।

अधिक पढ़ने के लिए, **यहाँ क्लिक करें**

संपर्क करें: ArchanaPandey@wateraid.org

ODF Plus पुडुचेरी

संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी ने 29 जुलाई 2023 को कराईकल और पांडिचेरी जिलों में अपने सभी 108 गांवों के लिए ODF Plus घोषित किया।

31 जुलाई 2023 तक 108 गांवों में से 92 ODF Plus उज्ज्वल श्रेणी में हैं, 4 ODF Plus उदयीमान हैं और 12 ODF Plus उत्कृष्ट श्रेणी में हैं। इसका मतलब है कि 107 गांवों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था है और 18 गांवों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त, DDWS के IMIS के अनुसार, राज्य में 108 अपशिष्ट संग्रहण और पृथक्करण शेड, 23 सामुदायिक सोख्ता गड्ढे, 108 सामुदायिक खाद गड्ढे, 11 सामुदायिक स्वच्छता परिसर और 2 कार्यशील गोबरधन संयंत्र हैं।

ODF Plus गांव वह होता है जो अपनी ODF स्थिति को बनाए रखता है और इसमें ठोस तथा तरल कचरे के प्रबंधन के लिए व्यवस्था होती है और यह दृष्टिगत रूप से स्वच्छ होता है।

अधिक पढ़ने के लिए, **यहाँ क्लिक करें**

संपर्क करें: ArchanaPandey@wateraid.org

निर्मल में भूजल पुनर्भरण के लिए मैजिक गड्ढों का संवर्धन

वर्षा जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देने के लिए, तेलंगाना के निर्मल जिले में वर्षा जल संचयन संरचनाओं का बड़े पैमाने पर निर्माण किया गया। 18 ब्लॉकों के 396 गांवों में 15 प्रति ग्राम पंचायत की दर से एक ही दिन में छत से वर्षा जल के संचयन हेतु कुल 5,940 संरचनाओं की संस्थापना की गई।

31 जुलाई, 2023 को चलाए गए इस अभियान के दौरान, हर छत को पानी के जलाशय या मैजिक गड्ढे जैसी रिचार्ज संरचना से जोड़ दिया गया था।

जिला कलेक्टर के नेतृत्व में की गई इस पहल को निर्मल जिले के जिला ग्रामीण विकास अधिकारी कोठापल्ली विजयलक्ष्मी द्वारा निष्पादित किया गया था। यह उल्लेखनीय है कि यह आयोजन एक दिन में संस्थापित सबसे अधिक रूफटॉप हार्वेस्टिंग संरचनाओं के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हेतु पात्र है।

इस आयोजन में जिला ग्रामीण विकास एजेंसी और पंचायती राज विभाग के कर्मियों की भागीदारी के साथ-साथ बड़े पैमाने पर सामुदायिक भागीदारी देखी गई, जिन्होंने समय पर कार्य पूरा करने के लिए मिलकर काम किया।

अधिक पढ़ने के लिए, **यहाँ क्लिक करें**

संपर्क करें: drda@py.gov.in

भागमंडला FSTP पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम का प्रभावी उपाय

कर्नाटक के कोडागु जिले के मदिकेरी ब्लॉक में हर मानसून में बाढ़ एक आम घटना है, जब भूजल स्तर जमीन के स्तर से 10-20 मीटर ऊपर तक बढ़ जाता है, जिससे मलीय पदार्थ बाढ़ के पानी के साथ मिल जाता है और अंततः कावेरी नदी में बह जाता है। इसका समाधान करने के लिए, मई 2022 में भागमंडला गांव में एक प्लांटेड ड्राईंग बेड-आधारित मलीय कीचड़ शोधन संयंत्र (FSTP) स्थापित किया गया था। इस यूनिट में प्रभावी रूप से पर्यावरण प्रदूषण का निवारण करते हुए सुरक्षित तरीके से मलीय पदार्थ का शोधन किया जाता है।

कर्नाटक के कोडागु जिले में मदिकेरी ब्लॉक में 26 ग्राम पंचायते हैं, जिनमें आवासीय इकाइयां, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, धार्मिक केंद्र और अन्य सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय शामिल हैं।

3,250.55 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले, भागमंडला में 1,034 घरों के 1,917 व्यक्तियों की आबादी है। यह ग्राम पंचायत एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल है, जो कावेरी नदी के स्रोत तालकावेरी के करीब स्थित है, जो लाखों परिवारों के लिए पानी प्रदान करता है। कोडागु के इस क्षेत्र में भारी वर्षा होती है, विशेष रूप से जून से सितंबर के महीनों के दौरान जब नदी ओवरफ्लो होती है, जिससे हर साल कम से कम 8 बार गांवों में बाढ़ आती है। यह उस समय के दौरान है जब नदी के पास स्थित घरों और सार्वजनिक शौचालयों से काला पानी और गंदला पानी नदी के पानी के साथ मिश्रित हो जाता है और उसे प्रदूषित करता है।

कर्नाटक का ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (RDWSD) गंदले और काले पानी के वैज्ञानिक निपटान के लिए एक FSTP स्थापित करने का इच्छुक था। एक प्रारंभिक सर्वेक्षण के बाद जब यह स्थापित किया गया कि नदी का संरक्षण और प्रदूषण को रोकना सभी की जिम्मेदारी थी तो नदी में गंदले और काले पानी के मिलने को रोकने के लिए RDWSD द्वारा एक कार्य योजना तैयार और अनुमोदित की गई थी।

कोडागु में 2.41 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित FSTP ग्रामीण कर्नाटक में कावेरी नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए इस तरह का पहला FSTP है।

अधिक पढ़ने के लिए, **यहाँ क्लिक करें**

संपर्क करें: sbmkodagu@gmail.com

राज्य के झरोखे से

सुश्री बेनु गुरुंग
मिशन निदेशक - SBM-G, सिक्किम

सिक्किम ODF Plus उत्कृष्ट (मॉडल) राज्य बन जाएगा

2003 में, सिक्किम ने खेती में रसायनों और कीटनाशकों के उपयोग को रोकने के उद्देश्य से जैविक खेती की ओर बढ़ने का संकल्प लिया। परिणामत: यह दुनिया का पहला जैविक राज्य बन गया और रोम में खाद्य और कृषि संगठन (FAO) द्वारा सम्मानित किया गया। SBM-G के पहले चरण के दौरान मई 2016 में राज्य को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया था।

राज्य के लिए सभी योजनाएं अब तैयार हैं, जो एक नाटकीय परिदृश्य के साथ हिमालय का एक हिस्सा है, जिसे 15 अगस्त 2023 तक ODF Plus मॉडल राज्य घोषित किया जाना है। हमारी योजनाओं के परिणामस्वरूप राज्य के आज सभी 403 गांव ODF Plus उत्कृष्ट श्रेणी में हैं। राज्य घरेलू स्तर पर बायोडिग्रेडेबल कचरे की खाद बनाने और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कारण ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के 100 प्रतिशत कवरेज का दावा करता है। यह देखते हुए कि राज्य भर में एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, इससे प्लास्टिक के उपयोग पर काफी अंकुश लगाया गया है। उत्पन्न होने वाले शेष प्लास्टिक कचरे के लिए, उचित निपटान तंत्र और फॉरवर्ड लिंकेज स्थापित किए गए हैं।

गोबरधन कार्यशाला में भाग लेते राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और CBG समर्थक उद्यमी

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को गोबरधन (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन) पहल से परिचित कराने और देश में बायोगैस/CBG की स्थापना की सुविधा प्रदान करने के लिए, जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (DDWS) ने 17 अगस्त 2023 को एक कार्यशाला का आयोजन किया।

गोबरधन, भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो 'समग्र विकास' के दृष्टिकोण पर आधारित है। DDWS, गोबरधन के लिए नोडल समन्वयन विभाग है, जिसका व्यापक उद्देश्य संपीड़ित प्राकृतिक गैस (CBG) और जैविक खाद (किण्वित जैविक खाद (FOM) और तरल किण्वित जैविक खाद (LFOM) दोनों) का उत्पादन करने और चक्रीय (Circular) अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए जैविक/बायोडिग्रेडेबल कचरे का वैज्ञानिक रूप से उपचार करना रहा है।

श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक, गोबरधन ने अपने स्वागत भाषण में, गोबरधन के लिए ऐसा संदर्भ निश्चित किया गया है, जिसमें अनेक लक्ष्य प्राप्त करने की संभावना शामिल तो है लेकिन यह ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने, आयात निर्भरता को कम करने, पराली जलाने को कम करने, और कृषि-अवशेषों, मवेशियों के अपशिष्ट आदि सहित शहरी/ग्रामीण बायोडिग्रेडेबल कचरे का प्रबंधन करने तक ही सीमित नहीं है, ये सभी भारत के जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

अधिक पढ़ने के लिए, **यहाँ क्लिक करें**

रिक्त स्थान भरें

मलीय कीचड़ प्रबंधन

1. सैप्टिक टैंक या शौच वाले गड्ढे से मलयुक्त कीचड़ निकालने की प्रक्रिया को _____ कहा जाता है
2. मूत्र, मल और फ्लश पानी के मिश्रण को _____ कहा जाता है
3. शौचालयों की रेट्रोफिटिंग में एकल गड्ढे वाले शौचालयों को _____ में परिवर्तित करना शामिल है
4. _____ को कोई मशीनीकृत निकासी, परिवहन या उपचार की आवश्यकता नहीं है
5. मलीय कीचड़ शोधन संयंत्रों के लिए तीन प्रौद्योगिकियां _____
6. DDWS FSM के लिए _____ सामंजस्यता को बढ़ावा देता है
7. एक उथला तालाब जहां ऑक्सीजन और सूरज की रोशनी की उपस्थिति में माइक्रोबियल कार्रवाई होती है, उसे _____ कहा जाता है

उत्तर:

1. डिस्लजिंग
2. मलीय कीचड़
3. दो गड्ढों वाले शौचालय
4. इन-सीटू शोधन
5. प्लांटिड ड्राइंग बेड, अनप्लांटिड ड्राइंग बेड, डीप रो इंट्रेंचमेंट
6. शहरी-ग्रामीण सामंजस्यता
7. पॉलिशिंग तालाब

स्वच्छता समाचार

सचिव की कलम से

4 लाख से अधिक गांवों द्वारा स्वयं को ODF Plus में घोषित करने के साथ-साथ, शहरी क्षेत्रों में मौजूदा STP के उन्नयन या रेट्रोफिटिंग और राज्यों के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं के विकास सहित शहरी-ग्रामीण सामंजस्यता को बढ़ावा देने के माध्यम से मलीय कीचड़ प्रबंधन पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है जिससे वे FSM को अपनी कार्य योजनाओं में एकीकृत करने में सक्षम बन सकें। मैं सभी राज्यों को FSM योजना और कार्यान्वयन को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करती हूं। ये ODF Plus भारत के विज़न को प्राप्त करने का केंद्रीय बिंदु हैं। इसके अतिरिक्त, निर्माणाधीन कार्यों के बारे में अधिक दृश्यता और जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए, ग्राम सभाओं के दौरान योजनाओं और मुद्दों पर चर्चा करने की आवश्यकता है ताकि समुदाय में सभी को, सभी कार्यों की जानकारी हो।

श्रीमती विनी महाजन
सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय

मिशन निदेशक की कलम से

एक ऐसी सर्कुलर इकॉनोमी का विचार जिसके द्वारा हम अपशिष्ट को एक नया जीवन देते हैं और सामग्रियों के उपयोग तथा पुन:उपयोग करने के विकल्प तलाशते हैं, जो ग्रामीण भारत में धरातल पर दृष्टिगत हो रहा है। यह गर्व की बात है कि देश के 2,100 से अधिक पंचायत समितियों में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयां हैं। हमारे समुदाय इस बात के प्रति जागरूक हो रहे हैं कि पर्यावरण अनुकूल विकल्पों का उपयोग करना न केवल आवश्यक है वरन ये सस्ते और सुलभ भी हैं। SDG लक्ष्यों की समय-सीमा पूर्व, नवीन अपशिष्ट प्रबंधन कार्यनीतियों को लागू करना और पर्यावरणीय रूप से स्थायी प्रयासों को पुनर्जीवित करना अनिवार्य है।

श्री जितेंद्र श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव और मिशन निदेशक (SBM-G)
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
जल शक्ति मंत्रालय

स्वच्छता समाचार के अगले अंक में योगदान करने के लिए, हर महीने की 15 तारीख से पहले **swachhbharat@gov.in** अपनी प्रस्तुति साझा करें।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
जल शक्ति मंत्रालय
भारत सरकार
DEPARTMENT OF DRINKING WATER AND SANITATION
MINISTRY OF JAL SHAKTI
GOVERNMENT OF INDIA
सत्यमेव जयते

विशेष सचिव का कार्यालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय
भारत सरकार।

चौथी मंजिल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, CGO कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
फोनः 011–24362192 | ईमेलः arun.baroka@nic.in